मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

मुंबई
वर्षः 7 अंक 97
शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2024
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshakti.co.in

हर खबर निष्पक्षता के साथ

अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सिटीजनशिप एक्ट धारा-6ए की वैधता बरकरार

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह प्रावधान 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों से संबंधित है, जो उन्हें भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है। हालाँकि, 25 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वाले अप्रवासी नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं।

26 मार्च, 1971 को बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के बाद सख्त आप्रवासन नियंत्रण की मांग तेज हो गई। छात्र संगठनों, विशेष रूप से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) और असम गण संग्राम परिषद (एएजीएसपी) ने बांग्लादेशियों की बढ़ती आमद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अप्रवासी. जवाब में, धारा 6ए को राजीव गांधी सरकार के तहत 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 'असम समझौते' के हिस्से के रूप में नागरिकता अधिनियम में शामिल किया गया था। इस प्रावधान का उद्देश्य 25 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले विदेशी

प्रवासियों की पहचान करके और उन्हें बाहर निकालकर इन समूहों की चिंताओं को दूर करना था।

धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान से अवैध अप्रवासियों की मौजूदगी ने असम के जनसांख्यिकीय संतुलन को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। याचिकाकताओं का दावा है कि स्वदेशी असमिया आबादी के अधिकार खतरे में हैं, यह दावा करते हुए कि धारा 6ए अनाधिकृत आप्रवासन को प्रभावी ढंग से वैध बनाती है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ उम्मीद है कि चंद्रचूड़ सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएंगे। इस फैसले का असम के जनसांख्यिकीय परिदृश्य और निवासियों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संवैधानिक अपराध : सिब्बल

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संवैधानिक अपराध है और अब इसका राज्य का दर्जा बहाल करने का समय आ गया है।

सिब्बल ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली चुनी हुई सरकार है।

अब्दुल्ला (54) ने पांच अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली जिनमें से तीन मंत्री जम्मू क्षेत्र के

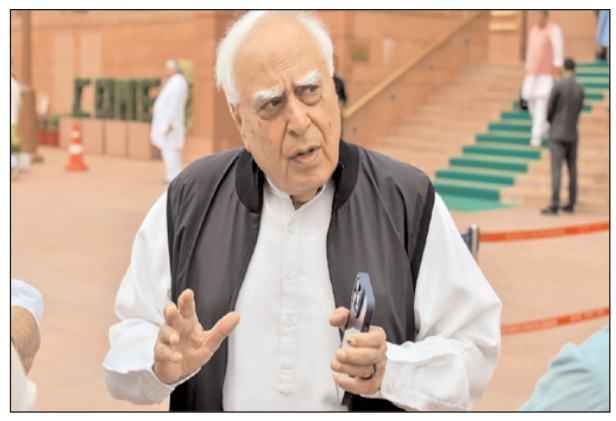

और दो कश्मीर घाटी के हैं। सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संवैधानिक अपराध था। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर फैसला नहीं करना गलत था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, राज्य का दर्जा बहाल करने का समय आ गया है। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों का संवैधानिक अधिकार है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

भारत की लॉजिस्टिक लागत दो साल में घटकर एकल अंक में आ जाएगी : नितिन गडकरी

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की लॉजिस्टिक लागत अगले दो साल में घटकर एकल अंक में आ जाएगी। नीति आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मंत्रालय कई राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, जिससे भारत की लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, दो वर्षों के भीतर हम अपनी लॉजिस्टिक लागत को नौ प्रतिशत तक कम करने जा रहे हैं। आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के अनुमानों के अनुसार, वित्त

वर्ष 2021-22 के लिए भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद के 7.8 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत के बीच थी।

गडकरी ने कहा कि भारत के लिए वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने निम्न गुणवत्ता वाले कोयला के मेथनॉल बनाने के लिए उपयोगी होने की बात को भी रेखांकित किया।

मंत्री ने साथ ही कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को विश्व में पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले वर्ष जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटर वाहन बाजार बन गया था और केवल अमेरिका तथा चीन से पीछे था। गडकरी ने कहा कि भारत के मोटर वाहन उद्योग का आकार 2014 में 7.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 18 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। यह उद्योग अधिकतम संख्या में रोजगार सृजन कर रहा है।

नायब सिंह सैनी ने भव्य समारोह में हरियाणा सीएम पद की ली शपथ

हरियाणा, 17 अक्टूबर। नायब सिंह सैनी ने आज दूसरी बार हरियाणा की कमान संभाल ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकूला में आयोजित भव्य समारोह में नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। सैनी मंत्रिमंडल में शामिल किये गये लोगों की बात करें तो आपको बता दें कि इनमें सबसे पहला नाम अनिल विज का है। इसके अलावा गौरव गौतम, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह, राणा कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, कृष्ण लाल पवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और आरती राव का नाम शामिल है।

हम आपको यह भी बता दें कि शपथ समारोह से कुछ घंटे पहले सैनी वाल्मीकि भवन गए और

उन्होंने पंचकूला स्थित गुरुद्वारे एवं मनसा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा की नयी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को तीव्र गति से आगे ले जाने की दिशा में काम करेगी। सैनी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि हरियाणा की जनता ने मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास दिखाया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र को पूरी तरह लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे 2014 के संकल्प पत्र और 2019 के संकल्प पत्र को देखें, हमने उन्हें पूरी तरह से लागू किया और अब हमारी सरकार इस संकल्प पत्र को भी लागू करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यह एक तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी था। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत हासिल कर भाजपा ने इतिहास रचा है इसीलिए एनडीए नेताओं का भी जोश देखते ही बन रहा है। सुबह चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर भाजपा और एनडीए नेताओं ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और विपक्षी गठबंधन खासकर कांग्रेस का सारा जोश अब उतर चुका है। हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेंगे।

इस सम्मेलन में विकास के मुद्दों, संविधान के 'अमृत महोत्सव' और आपातकाल के संदर्भ में लोकतंत्र की 'हत्या की कोशिश' के 50 साल पूरे होने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की उल्लेखनीय जीत के बाद विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पर सत्तारूढ़ गठबंधन के नए हमले के रूप में देखा जा रहा है।

बिहार में धड़ल्ले से जारी है जहरीली शराब का अवैध कारोबार, सरकार को लगाम लगानी चाहिए : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बिहार के सीवान एवं सारण जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत पर बृहस्पतिवार को दुख जताया और आरोप लगाया कि प्रदेश में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए।

बिहार के सीवान और सारण जिलों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से बुधवार को छह लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, बिहार के सीवान और सारण जिलों में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की

मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्रीचरणों में स्थान दें। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। उन्होंने कहा, बिहार में शराबबंदी लागू है लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है जिससे आये दिन मौतें होती हैं। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए।

देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कौन होगा उत्तराधिकारी?

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले शुक्रवार को निवर्तमान सीजेआई को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार सिफारिश करने को कहा गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने 17 दिसंबर, 2022 को पद की शपथ ली और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। शपथ लेने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। सीजेआई के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति खन्ना का जनवरी 2019 में शीर्ष अदालत में पदोन्नत होने के बाद से एक उल्लेखनीय न्यायिक करियर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति ने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने उम्र और उम्र दोनों में 33 वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज कर दिया था। अनुभव। हालाँकि,

उनकी नियुक्ति के कुछ महीनों के भीतर ही यह मुद्दा शांत हो गया। प्रसिद्ध न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना के भतीजे, न्यायमूर्ति खन्ना, जिन्होंने आपातकाल के दौरान विरोध में इस्तीफा दे दिया था, ने अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले खन्ना ने 14 वर्षों तक दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। उन्हें कराधान, वाणिज्यिक कानूनों में उनकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है और उन्होंने पिछले दो दशकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। 14 मई, 1960 को जन्मे खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और 1983 में प्रैक्टिस शुरू की। शुरूआत में दिल्ली की जिला अदालतों में शुरूआत की, बाद में वह संवैधानिक कानून, मध्यस्थता, प्रत्यक्ष कर, कंपनी पर काम करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में स्थानांतरित हो गए।

जांच एजेंसियों को किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं करना चाहिए काम: सिद्धारमैया

कर्नाटक, 17 अक्टूबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिद्धारमैया ने कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए और एक पार्टी के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य में तीन विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का सामना करने और जीतने के लिए तैयार है।

अपने बयान में सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश में नवंबर में होने वाले उपचुनाव का कांग्रेस पार्टी प्रभावी ढंग से मुकाबला करेगी और सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सीबीआई, ईडी और आईटी सहित सभी संगठनों को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नागेंद्र (पूर्व मंत्री बी नागेंद्र) ने मीडिया से कहा है कि उन पर ईडी ने दबाव डाला था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उन पर मेरा और डी के शिवकुमार (उपमुख्यमंत्री) का नाम लेने का

दबाव डाला गया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र ने बुधवार को जेल से बाहर आने पर आरोप लगाया कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम (केएमवीएसटीडीसी) में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का नाम लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर दबाव डाला था। उन्होंने ईडी पर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दबाव में उन्हें गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया। यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कांग्रेस विधायक को जमानत दे दी। उन्हें घोटाले के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

जम्मू-कश्मीर में महका लोकतंत्रः सरकार से बड़ी उम्मीदें

-ललित गर्ग

आखिरकार जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की धूप खिल ही गयी, पांच साल बाद केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर को निर्वाचित सरकार मिल गयी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के बाद केन्द्र शासित प्रदेश में यह पहली चुनी हुई सरकार है, जो नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है। उमर अब्दुल्ला पहले भी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी यह पारी हर तरह से खास है। नई सरकार के मुखिया के तौर पर उमर अब्दुल्ला के सामने आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कठिन चुनौती भी है। जनता ने विकास और शांति की आकांक्षा के साथ दिल खोलकर मतदान किया और अपनी उम्मीदों की सरकार चुनी है। घाटी में दशकों तक अब्दुल्ला परिवार के शासन के अनुभव के मद्देनजर घाटी के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताया। तमाम ऊहापोह, सुरक्षा चुनौतियों तथा विदेशी दखल की तमाम आशंकाओं को निर्मूल करते हुए जम्मू-कश्मीर के जनमानस ने स्पष्ट सरकार बनाने का जनादेश दिया है। इस भूमिका तक

पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। कश्मीर में विकास, पर्यटन में भारी वृद्धि, शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनना ऐसे ही प्रयासों की सार्थक निष्पत्ति है। नई सरकार को विकास की चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए आतंकमुक्त कश्मीर के संकल्प को मंजिल तक पहुंचाना होगा।

जम्मू एवं कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार का गठन अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेगा बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। बहरहाल, ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार और केंद्र का दायित्व है कि घाटी के लोगों ने जिस मजबूत लोकतंत्र की आकांक्षा जतायी है, उसे पूरा करने में भरपूर सहयोग करें। एक समय राज्य में मतदाता डर कर मतदान करने हेतु नहीं निकलते थे। मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहता था। इस बार मतदाता निर्भीकता के साथ मतदान करने निकले। जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के संकल्प को सकारात्मक समर्थन दिया है। यद्यपि लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी नहीं मिल पायी थी, लेकिन जनता ने उन्हें राज्य में सरकार चलाने का स्पष्ट जनादेश दिया है। वहीं दूसरी ओर, इस भारी मतदान व स्पष्ट बहुमत का एक निष्कर्ष यह भी है कि लोग घाटी में शांति और सुकून, अमन एवं विकास, सौहार्द एवं सद्भावना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा कि इस क्षेत्र में शांति कायम होने के साथ विकास की नई बयार चले। जिसमें आम नागरिक खुद को सुरक्षित अनुभव करते हुए राष्ट्रीय विकास की धारा के साथ-साथ कदमताल कर सके।

निश्चित ही उमर के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, आम लोगों को भी उनकी कठिनाइयों का अंदाजा है, वहीं खुद उमर ने भी व्यावहारिक नजरिया अपनाने का संकेत दिया है। चुनाव के दौरान अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग पर कड़ा रुख अपनाने वाले उमर ने चुनाव नतीजे आने के बाद इस मसले पर अपना रुख नरम कर लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं, जिनमें इस मुद्दे पर जोर देने का किसी को कुछ फायदा होगा। उम्मीद बढ़ाने वाली बात यह भी है कि चुनावी कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए सभी पक्षों ने सहयोग का रुख अपनाने का संकेत दिया है। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई सरकार के साथ मिलकर काम करने का संकेत दिया है बल्कि खुद उमर ने भी उपराज्यपाल से टकराव की बजाय आपसी समझ एवं सकारात्मकता से शासन करने की मंशा जतायी है, जो जहां जम्मू-कश्मीर की जनता के हित में है वही उमर की राजनीतिक सूझबूझ, परिपक्वता एवं विवेक का परिचायक है। चाहे उपमुख्यमंत्री पद जम्मू संभाग से चुने गए विधायक सुरिंदर चौधरी को स्थान देने की बात हो या कांग्रेस के लिए कैबिनेट में स्थान खाली रखने की, उमर अब्दुल्ला यह संकेत दे रहे हैं कि वह सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस ने फिलहाल सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कही है, लेकिन इसका कारण राज्य का दर्जा न मिलने को बताया है। उमर को हर कदम सावधानी से उठाने होंगे ताकि कोई भी स्थिति मंत्री पदों की संख्या का या इंडिया गठबंधन के घटक दलों में मतभेद एवं टकराव का न बन जाए। उमर के एक-एक फैसले पर कैबिनेट और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का मसला सामने आ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इन सबके बीच जम्मू-कश्मीर की नई सरकार उमर के नेतृत्व में कितने सधे कदमों से आगे बढ़ती है। क्योंकि सरकार को अपना दायित्व इस बात को ध्यान में रखकर निभाना होगा कि केंद्रशासित प्रदेश में उपराज्यपाल के पास व्यापक अधिकार हैं।

केंद्र शासित प्रदेश में एक दशक बाद हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का खासा उत्साह लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूती दे रहा है। कहीं न कहीं जनता ने स्पष्ट संदेश भी दिया कि वे हिंसा, अस्थिरता, आतंकवाद व अलगाववाद से छुटकारा चाहते हैं। जाहिरा तौर पर नई सरकार के सामने व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने की चुनौती होगी। इसलिये जम्मू-कश्मीर में नई सरकार को व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए बदली हुई शासन व्यवस्था के साथ भी साम्य स्थापित करना है। इस बात का अहसास उमर अब्दुल्ला को भी है कि शासन चलाने में अब पहले जैसी स्वतंत्रता नहीं होगी। विश्वास किया जाना चाहिए कि कम से कम सीमावर्ती घाटी की संवेदनशीलता को देखते हुए इस केंद्रशासित प्रदेश में वैसा टकराव देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच देखने को मिलता रहा है। विश्वास करें कि नई सरकार को प्रशासनिक मामलों में नौकरशाही का पर्याप्त सहयोग मिलता रहेगा। नीति-नियंताओं को ध्यान रखना होगा कि सरकार चलाने में किसी भी तरह का अनावश्यक व्यवधान कालांतर अशांति का वाहक बनेगा। उम्मीद करें कि यथाशीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रशासन की विसंगतियां दूर की जा सकेंगी।

राज्य ने साम्प्रदायिकता, आतंकवाद तथा अस्थिरता के जंगल में एक लम्बा सफर तय किया है। उसकी मानसिकता घायल है तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, उसमें नई उम्मीदों को पंख लगे हैं। अलगाव से बाहर निकलने का नया विश्वास जगा है। पाकिस्तानी आतंकी सोच के नुकसान को प्रांत ने झेला और महसूस किया है। गुलाम कश्मीर के लोगों की दुर्दशा को देखा जा रहा है। इसीलिये इन चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर और बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतांत्रिक सरकार बनायी है, जो शांति और विकास के नये द्वार उद्घाटित करते हुए युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करे एवं आतंकमुक्ति का एक नया अध्याय रचे। आज सबकी आंखें एवं कान उमर की भविष्य के शासन एवं नीतियों पर टिकी है। निश्चित ही इस नई सरकार से उम्मीद जगी है कि उसके प्रयासों से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक विकास और शांति-समृद्धि-स्थिरता का नया दौर शुरू होगा। ऐसा होना ही नई सरकार एवं उमर के नेतृत्व की सार्थकता है।

अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर क्यों टिकी हैं चीन की नजरें ?

अशोक भाटिया

1950 के दशक के आखिर में तिब्बत को अपने में मिलाने के बाद चीन ने अक्साई चिन के 38000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था, यह इलाका लद्दाख से जुड़ा थे। यहां पर चीन ने नेशनल हाईवेज 219 बनाया, जो उसके पूर्वी प्रांत शिनजियांग को जोड़ता है और भारत इसे चीन का अवैध कब्जा मानता है। वैसे तो चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खास दिलचस्पी तिब्बत और भूटान की सीमा से लगे हुए तवांग में सबसे ज्यादा है।कुछ समय पूर्व तवांग में चीनी सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे थे जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया और खदेड़ दिया। लेकिन चीन की तवांग में क्या दिलचस्पी है? 1914 में ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें बॉर्डर से जुड़े अहम फैसले लिए गए। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर की सीमा खींची गई। इसके तहत तवांग (अरुणाचल प्रदेश) को भारत का हिस्सा माना गया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा गया। चीन के प्रतिनिधियों ने तत्काल वाले मैप पर तो साइन किए लेकिन बाद में डिटेल्ड मैप पर साइन नहीं किए।चीन इसके बाद से कहता है कि उसे धोखे और अंधेरे में रखते हुए मैकमहोन रेखा खींची गई। यही कारण है कि चीन मैकमहोन लाइन को मानने से इनकार करता रहता है। चीन का कहना है कि भारत और चीन के बीच आधिकारिक तौर पर बॉर्डर कभी तय ही नहीं हुआ। चीन का मानना है कि तिब्बत कोई संप्रभु देश नहीं है जो बॉर्डर को लेकर किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करे। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता है और उसे दक्षिणी तिब्बत बताता है।तवांग का सामरिक तौर पर बहुत अहम स्थान है। राजधानी ईटानगर से करीब 450 किलोमीटर दूर तवांग अरुणाचल प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तवांग चीन के साथ ही भूटान के साथ भी बॉर्डर साझा करता है।

हिमालय के फुटहिल्स में स्थित भारत के इस क्षेत्र को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। यह ब्रिटिश इंडिया के राजनैतिक विभाजन में से एक थी और 1972 तक इसे इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद 20 जनवरी 1972 को इसे भारतीय गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को अंततः 20 फरवरी 1987 को भारत का 24वां राज्य घोषित किया गया। यह उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर दक्षिण में ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। अगर एरिया वाइज देखें तो 8374 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ अरुणाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ-ईस्ट रीजन में सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही भौगोलिक क्षेत्र का अधिकांश भाग भूमि है, जो 98 प्रतिशत जंगल और 2 प्रतिशत पानी से घिरा हुआ है। यह राज्य भूटान, तिब्बत और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है।

1914 के शिमला समझौते ने ईस्टर्न सेक्टर में एलएसी के साथ अलाइन करते हुए मैकमोहन लाइन को ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच नई सीमा के रूप में परिभाषित कर दिया था। यह नाम ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच हुए शिमला कन्वेंशन के तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच सीमा के रूप में 890 किलोमीटर की एक रेखा खींच दी थी। हालांकि अंत में चाइना ने इस लाइन को स्वीकार नहीं किया और यह समझौता ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच साइन किया गया था। चूंकि तिब्बत तब चाइना से अलग हुआ करता था, इस संधि के लिए चाइना के रिप्रेजेंटेशन की तब कोई जरूरत नहीं थी और इस संधि के द्वारा तिब्बत ने तवांग सहित अपने दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था।

भारत के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बन जाता है। जोकि दूसरी तरफ चाइना के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है। यदि चाइना भविष्य में तवांग पर आक्रमण करने में सफल होता है तो यह रास्ता चाइना को भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकनस नेक तक पहुंचने में एक आसान रास्ता भी प्रदान करेगा। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भूमि का एक नैरो स्ट्रेच है, जो भारत को अपने ईस्टर्न राज्यों से जोड़ता है और इस वजह से यह भी एक रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। यदि हम भौगोलिक निकटता से देखें तो तवांग एक लैंड लॉक्ड रीजन भी है। इसके नॉर्थ में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, साउथ वेस्ट में भूटान और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कमिंग जिला से अलग हुई सेला पास है और इस प्रकार यहां एक ट्राई जंक्शन बनता है। तवांग पर कब्जा करने के लिए चाइनीज सोल्जर्स को सेला पास तक पहुंचना होगा। सेला पास आने के लिए उन्हें तवांग में स्थित येंगजी क्षेत्र से होकर आगे आना होगा। इसके अलावा येंगजी में 17000 फीट ऊंची एक चोटी है, यह शिखर वर्तमान में भारत के नियंत्रण में आता है, जो बॉर्डर के दोनों तरफ एक शानदार दृश्य प्रदान करता है और इसीलिए भारत फायदे की स्थिति में रहा है।

तवांग में दुनिया का दूसरा सबसे तिब्बती बौद्ध मठ है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा के बाद सबसे बड़ा। इसे मठ को बेहद पवित्र माना जाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह मठ चीनी शासन से दूर रहने के कारण अब तक अपने शुद्ध रूप में है। तवांग तिब्बती संस्कृति के अंतिम बचे केंद्रों में से एक है। जब चीनी सैनिक तिब्बत को तबाह कर रहे थे तो इस मठ ने कई अमूल्य पांडुलिप और पुराने शास्त्रों को बचाया है। तवांग मठ देवता पालदेन ल्हामो या देवी द्री देवी को समर्पित है, जिन्हें तिब्बत का प्रमुख संरक्षक माना जाता है। मान्यता है कि यदि यह मठ गिर जाता है तो तिब्बत और तिब्बती बौद्ध धर्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तवांग तिब्बती बौद्ध केंद्र का आखिरी सबसे बड़ा गढ़ है जिसे चीन सालों से नष्ट करना चाहता है। इस मठ की विरासत बीजिंग और नई दिल्ली के बीच टकराव का केंद्र रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन जानबूझकर तवांग सेक्टर में झड़पों को अंजाम देकर भारत की सैन्य तैयारियों की जांच करता है।

गौरतलब है कि लद्दाख और अरुणाचल में चीन आज भी लगातार भारत को उकसाने वाली हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा क्योंकि वह चाहता है कि उकसाने में आकर भारत कोई ऐसी कार्रवाई करे, जिसका फायदा वो उठा सके। चीन का अरुणाचल के बड़े हिस्सों पर अपना दावा जताना कोई नई बात नहीं। वह पहले भी हमारे कई नेताओं तक की अरुणाचल यात्रा पर कई बार विरोध कर चुका है। यद्यपि अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में वर्ष 1987 में ही अस्तित्व में आया। उससे पहले 1972 तक इसे नार्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था लेकिन 20 जनवरी, 1972 को इसे केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। उसके बाद पिछले तीन दशक में पूर्व में स्थित अनजान से लेकर राज्य के पश्चिम में स्थित तवांग तक ह्यलाइन ऑफ एकचुअल कंट्रोलह्व के आसपास 1126 किलोमीटर के इलाके के पास चीन की गतिविधियों के निरंतर बढ़ते रहने की बात सामने आने लगी। 1986 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास चीनी सेना की बनाई स्थाई इमारतें देखीं तब पहली बार इस क्षेत्र में भारतीय सेना सक्रिय हुई और उसने हाथुंगला पर अपनी तैनाती को मजबूत कर लिया। तब चीन इस कदर बौखला गया और दोनों देशों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। मामला तब शांत हुआ था जब तत्कालीन विदेश मंत्री नारायण दत्त तिवारी बीजिंग पहुंचे। लेकिन बाद के सालों में चीन ने बहुत आक्रामकता दिखाई। उसने दिवगंत घाटी में पोस्टर लगाकर उस पूरे इलाके को ही चीन के अधीन बता दिया था।

भारत-चीन सीमा विवाद पर बैठकों की लम्बी यात्रा के दौरान चीन ने अरुणाचल को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। उसने अरुणाचल के लोगों को भावनात्मक स्तर पर भारत से तोड़ना चाहा। उसने स्पष्ट संदेश दिया कि अरुणाचल के लोग चीन के ही नागरिक हैं। उसने अरुणाचल के युवाओं को बिना वीजा चीन में प्रवेश देकर यह संदेश दिया था की जब आप चीन के ही नागरिक हैं तो फिर वीजा की क्या जरूरत है। चीन की नजरें अरुणाचल के तवाऊं शहर में तवांग मठ पर हैं। 15वें दलाई लामा का जन्म यहीं हुआ था। तवांग मठ सबसे प्रमुख बौद्ध स्थल है। चीन तवांग को लेकर तिब्बत की तरह प्रमुख बौद्ध स्थलों पर मजबूत पकड़ बनाना चाहता है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग मठ पर भी कब्जा कर लिया था लेकिन बाद में उसे यहां से वापिस लौटना पड़ा था। तब से ही उसकी नजरें तवांग पर अटकी हुई हैं। दरअसल अरुणाचल के लिए तवांग भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर भारत की पकड़ उस पर कमजोर हुई तो सामरिक रूप से हमें काफी नुक्सान हो सकता है।

चीन भी जानता है कि भारत की सैन्य ताकत अब कमजोर नहीं है। भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अब सवाल यह है कि अगर चीन अरुणाचल पर कब्जा करना चाहता था तो फिर1962 की लड़ाई में वो इससे पीछे क्यों हट गया? हलाकि 62 युद्ध के समय तो भारत काफी कमजोर था। हालांकि बाद में उसने अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का इलाका कहना शुरू कर दिया। चीन यह भी जानता है कि अरुणाचल के लोग कभी उसके समर्थन में नहीं खड़े हुए। चीन ने भारत के वास्तविक नियंत्रण सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव भी बसा लिया है। इसके जवाब में भारत की तरफ से भी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। बातें बहुत कड़वी हैं, मैं यहां आर्थिक, वाणिज्य या साफ्टवेयर, हार्डवेयर की बात नहीं करना चाहता। जिस धूर्तता और चतुराई के साथ भारत के साथ व्यापार बढ़ाया और भारतीय बाजारों का फायदा उठाया उसको समझने की जरूरत है। ड्रेगन को जवाब उसी की भाषा में देना होगा। भारत को अपनी सामरिक शक्ति को और बढ़ाना होगा ताकि हम किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे सकें।अभी हमारे देश में त्योहारों का सीजन है , हम चीनी मालों का पूर्ण बहिष्कार कर ड्रेगन के व्यापार की चैन को तोड़ सकते है व उसे सबक सीखा सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सौ वर्षीय यात्रा पर एक नजर

डा. हेडगेवार ने संगठन को देश की राष्ट्रीय आवश्यकता कहा था। उन्होंने कोलकाता में क्रांतिकारियों और नागपुर में कांग्रेस के साथ काम कियाय पर संघ स्थापना के बाद पूरी शक्ति यहीं लगा दी। इसलिए पहले 50 साल संघ ने केवल संगठन किया।

2025 की विजयादशमी पर संघ सौवें वर्ष में पहुंच रहा है। ऐसे में इस यात्रा के कुछ पड़ावों पर नजर डालना उचित होगा। डा. हेडगेवार ने संगठन को देश की राष्ट्रीय आवश्यकता कहा था। उन्होंने कोलकाता में क्रांतिकारियों और नागपुर में कांग्रेस के साथ काम कियाय पर संघ स्थापना के बाद पूरी शक्ति यहीं लगा दी। इसलिए पहले 50 साल संघ ने केवल संगठन किया। यद्यपि अन्य बहुत कुछ भी शीर्ष नेतृत्व के मन में था। दत्तोपंत ठेंगड़ी इसे 'प्रोगेसिव अनफोल्डमेंट' कहते थे। इसके बल पर ही संघ ने हर संकट को झेला।

इस पहले दौर में स्वयंसेवकों ने कई संस्थाएं बनायीं। इनमें राष्ट्र सेविका समिति (1936), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (1949), वनवासी कल्याण आश्रम (1952), भारतीय मजदूर संघ (1955), विश्व हिन्दू परिषद (1964), भारतीय जनसंघ/भारतीय जनता पार्टी (1951), सरस्वती शिशु मंदिर/विद्या भारती (1952) आदि प्रमुख हैं। यद्यपि इनके संविधान, कोष, पदाधिकारी, कार्यक्रम आदि अलग हैंय पर प्रेरणा संघ की ही है।

संघ पर प्रतिबंधः संघ पर 1932 और 1940 में शासन ने आंशिक प्रतिबंध लगायेय पर वे ज्यादा नहीं चले। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद फिर प्रतिबंध लगा। तब शासन, प्रशासन और जनता संघ के विरोध में थी। प्रचार माध्यम सरकार के पास थे। संघ के पास अपनी बात कहने का कोई साधन नहीं था। फिर भी संघ ने सत्याग्रह से सरकार को झुका दिया।

पर फिर शाखा के साथ ही समविचारी संगठनों का विस्तार और प्रभाव बढ़ने लगा। इसीलिए जब 1975 में इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, तो जनता संघ के साथ रही। संघ ने फिर सत्याग्रह किया। जनता डर से चुप थी, पर चुनाव में उसका आक्रोश फूट पड़ा और इंदिरा गांधी हार गयी। यह संगठन के बल पर ही हुआ। समाज में बढ़ती स्वीकार्यता का लाभ उठाकर संघ ने संगठन को फैलाया तथा स्वयंसेवकों ने अनेक नयी संस्थाएं बनायीं।

1992 में बाबरी विध्वंस के बाद सरकार ने फिर प्रतिबंध लगाया, जिसे न्यायालय ने ही खारिज कर दिया। 1975 और 1992 के प्रतिबंध से संघ के संगठन और प्रभाव में वृद्धि हुई। उसका नाम दुनिया भर में फैल गया।

1977 के बादः इसे हम दूसरा 50 वर्षीय कालखंड कह सकते हैं। संघ ने अनुभव किया कि हमारा काम समाज के निर्धन वर्ग में नहीं है। इनकी पहली जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। इस कारण लोग धर्मांतरण भी कर लेते हैं। मीनाक्षीपुरम् कांड इसका उदाहरण था। अतः सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया गया। 1989 में डा. हेडगेवार की जन्मशती पर 'सेवा निधि' एकत्र कर हजारों पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाये गये। निर्धन बस्तियों को 'सेवा बस्ती' कहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हजारों छोटे प्रकल्प शुरू किये। अब इनकी संख्या डेढ़ लाख से भी अधिक है। अब सैकड़ों बड़े प्रकल्प भी हैं, पर मुख्य ध्यान छोटी इकाइयों पर ही है। केवल संघ ही नहीं, तो सभी समविचारी संस्थाएं सेवा कार्य कर रही हैं। यहां से पुरुष और महिला कार्यकर्ता भी आगे आ रहे हैं।

कुछ चुनौतियांः 1947 में देश विभाजन एक बड़ी चुनौती थी। इस दौरान पंजाब और सिंध में संघ ने सीमित शक्ति के बावजूद लाखों हिन्दुओं की रक्षा की, महिलाओं की लाज बचाई और उनका पुनर्स्थापन किया। बंगाल में शक्ति कम होने से यह प्रभावी ढंग से नहीं हो सका।

1950 में प्रतिबंध हटने पर कुछ लोगों का विचार था कि निर्दोष होते हुए भी संसद या किसी विधानसभा में कोई हमारे पक्ष में नहीं बोला। अतः हमें शाखा छोड़कर केवल राजनीति करनी चाहिएय पर सरसंघचालक श्री गुरुजी नहीं माने। उन्होंने कहा कि राजनीति जरूरी होते हुए भी सब कुछ नहीं है। इससे कई बड़े लोग नाराज हो गये। यद्यपि संघ ने फिर राजनीति में भी कई लोगों को भेजा, पार्टी भी बनायी, पर राजनेताओं और दलों का जो हाल है, उससे श्री गुरुजी की बात प्रमाणित हो रही है।

संगठन होने के कारण संघ तथा संघ प्रेरित संस्थाएं लगातार नयी टीम बनाकर पुरानों के संरक्षण में उन्हें पदस्थापित करते रहते हैं, पर 1968 में भारतीय जनसंघ को एक झटका लगा। दीनदयाल जी का निधन हो चुका था। जनसंघ वाले अटल बिहारी वाजपेयी को आगे लाना चाहते थे। इससे रुष्ट होकर बलराज मधोक ने पार्टी छोड़ दी, पर जल्दी ही वे समझ गये कि कुछ लोग कुछ समय के लिए कोई संस्था तो चला सकते हैं, पर संगठन नहीं। अतः वे शांत होकर फिर संघ के कार्यक्रमों में आने लगे। यद्यपि उनके अलगाव से श्री गुरुजी सहित सब स्वयंसेवकों को दुख हुआ, पर संघ में व्यक्ति नहीं, संगठन महत्वपूर्ण है।

ऐसी ही एक चुनौती 2018 में विश्व हिन्दू परिषद में आयी। एक प्रभावी नेता ने अपनी नयी संस्था बना ली। यहां भी टकराव व्यक्ति और संगठन में ही था। आशा है वे भी शीघ्र ही मुख्य धारा में लौट आएंगे।

अब आगे की ओरः कभी 'संगठन के लिए संगठन' की बात कही जाती थी, पर 50 साल संगठन और 50 साल विस्तार के बाद अब संघ समाज परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जहां संघ का काम पुराना है, वहां परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, सामाजिक समरसता, एक मंदिर, एक शमशान, एक जलस्त्रोत, नागरिक कानूनों के पालन आदि का आग्रह किया जा रहा है। संघ के प्रयास से इस दिशा में भी निःसंदेह सुधार होगा। समाज में हजारों संस्थाएं और लोग अच्छे काम कर रहे हैं। संघ उन्हें भी साथ लेकर सम्मान और श्रेय देता है। संस्थागत अभिनिवेश से मुक्ति संघ की एक बड़ी विशेषता है।

यद्यपि जब से भाजपा की सरकारें केन्द्र और राज्यों में बन रही हैं, तब से संघ में बहुत भीड़ भी आने लगी है। नये लोगों का आना सुखद है, पर जो स्वार्थवश आ रहे हैं, उनसे सावधान रहना होगा। 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे' से लेकर 'परम वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्' की इस अविराम यात्रा में बहुत काम बाकी है। निरूसंदेह अगले कुछ वर्ष में करोड़ों स्वर 'भारत माता की जय' बोलेंगे और विश्वगुरु भारत का सपना साकार होगा।

- विजय कुमार

किसान आंदोलन के नाम पर हुए बवाल का जो सच सामने आया है उससे देश को सतर्क हो जाना चाहिए

जाहिर है कांग्रेस पार्टी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से किनारा ही करेगी लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों के नाम पर खड़ा किया गया आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक था और इसका एकमात्र मकसद मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना था।

देश ने हाल के कुछ वर्षों में कई आंदोलन देखे। सबसे पहले जन लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को मिले समर्थन के बलबूते अरविंद केजरीवाल सत्ता की सीढ़ियां चढ़ कर अपनी मंजिल पर पहुँच गये लेकिन दिल्ली में जन लोकपाल नहीं बनाया। देश ने दिल्ली में हरियाणा के कुछ पहलवानों का आंदोलन भी देखा। यह पहलवान राजनीति के अखाड़े में कूदने के लिए उसी खेल को नुकसान पहुँचाते रहे जिसकी बदौलत उन्होंने दौलत और शोहरत कमाई। देश ने किसान आंदोलन भी देखा। किसानों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य के लिए मोदी सरकार जो तीन कानून लेकर आई उसके बारे में भ्रम फैला कर देशभर में किसानों का आंदोलन खड़ा कर दिया गया जिसके चलते सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। खुद को किसान कहने वाले आंदोलनकारियों ने कानून व्यवस्था का भी खूब मजाक बनाया और सरकार को झुकाने का अभियान सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया। मगर अब इस किसान आंदोलन का सच एक प्रमुख आंदोलनकारी ने ही देश के सामने रख दिया है।

हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि किसानों ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया था। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि किसानों ने हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, लेकिन पार्टी ने सब कुछ वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर छोड़ दिया था। संयुक्त संघर्ष पार्टी के संस्थापक चढ़ूनी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यही बताया है। चढ़ूनी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गयी है और भाजपा ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग भी की है। जाहिर है कांग्रेस चढ़ूनी के बयान से किनारा ही करेगी लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों के नाम पर खड़ा किया गया आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक था और इसका एकमात्र मकसद मोदी सरकार को सत्ता से

बाहर करना था। समय-समय पर इस आंदोलन से जुड़े तमाम सच सामने आते ही रहे हैं। टूलकिट गैंग के सदस्यों ने भोले भाले किसानों को बरगला कर अपने राजनीतिक हित तो साध लिये मगर अन्नदाता का नुकसान करवा दिया।

आम किसानों का कैसे अपने राजनीतिक हितों के लिए इन तथाकथित किसान नेताओं ने दुरुपयोग किया यह हमने लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखा था। तीनों कृषि कानून काफी पहले ही यानि साल 2022 के अंत में ही वापस लिये जा चुके थे लेकिन उसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान पंजाब में भाजपा के सभी उम्मीदवारों के घर के बाहर बड़ी संख्या में किसानों को धरने पर बैठा दिया गया था। पंजाब में चुनाव प्रचार की कवरेज के दौरान जब मैंने संगरूर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला आदि क्षेत्रों में धरने पर बैठे लोगों से पूछा कि आपकी मांगें क्या हैं तो सबका जवाब एक ही था कि सारी समस्याओं के हल तक हम यहां से नहीं हटेंगे। जब मैंने पूछा कि समस्याएं क्या हैं तो हर जगह से यही जवाब मिला कि स्कूल अच्छे बनने चाहिए, अस्पतालों में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए। स्पष्ट था कि यह धरना प्रदर्शन भी एक टूलकिट का हिस्सा था। लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होते ही यह प्रदर्शनकारी भाजपा उम्मीदवारों के घर के बाहर से हट गये। ऐसा लगा कि उनकी सारी समस्याओं का या तो समाधान हो गया है या टूलकिट के तहत दिया गया टास्क पूरा हो गया है।

वैसे जहां तक चढ़ूनी की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने हरियाणा में कुरुक्षेत्र की पेहोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। यहां जनता ने मात्र 1170 वोट देकर उनकी जमानत तक जब्त करा दी। हम आपको यह भी याद दिला दें कि इन तथाकथित किसान नेताओं ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में भी किस्मत आजमाई थी। पंजाब की 31 में से 22 किसान यूनियनों ने संयुक्त समाज मोर्चा नामक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया था। लेकिन एक को छोड़कर इनके बाकी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाये थे। अब हरियाणा में भी इस पार्टी का जो हश्र हुआ है उससे साफ है कि आम जनता और आम किसानों का समर्थन इन लोगों के पास कभी भी नहीं था। विदेशी इशारे पर और विदेशी पैसे के बलबूते भारत की छवि को खराब करने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया था उसका सच सामने आ चुका है। यह समय है कि देश सतर्क हो जाये और गैर-राजनीतिक आंदोलनों की असली मंशा को पहचाने।

बहरहाल, चढ़ूनी के बयान पर हमलावर होते हुए भाजपा ने कहा है कि जिस किसान आंदोलन को सहज और स्वाभाविक बताया गया था, वह दरअसल कांग्रेस की ओर से प्रायोजित और पोषित था। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि चढ़ूनीजी का जो वक्तव्य आया है, उसने एक बार फिर उजागर कर दिया है कि कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि जिस आंदोलन को सहज और स्वाभाविक आंदोलन कहा जा रहा था, वह कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था।

-नीरज कुमार दुबे

हर्षोल्लाश से मनाया गया समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद यादव का जन्मदिन

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी के भिवंडी जिला कमेटी सदस्य अरविन्द यादव का जन्मदिन उनके शुभचिंतकों ने बडे धूमधाम से केक काटकर मनाया। बतादें कि पिछले कई वर्षों से भिवंडी तालुकाध्यक्ष के पद पर एक जुझारू नेता की तरह कार्य करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है जिसको देखते हुये महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू हासिम आजमी ने अरविंद यादव को भिवंडी जिला कमेटी में सदस्य पद पर नियुक्त किया है। अरविन्द यादव का जन्मदिन उनके शुभचिंतकों द्वारा उनके निवास के पास काटई स्थित बडे धूमधाम से पटाखे फोडकर डी जे बजाकर, केक खिलाकर मनाया गया। इस अवसर पर सपा भिवंडी महिला जिलाध्यक्ष सुगीदेवी यादव, समाजसेविका सुमन यादव, अंजली यादव, पत्रकार आचार्य सूरजपाल यादव, इंद्रजीत यादव, अजय यादव, बबलू चौधरी, संजय चौधरी, अरविंद धीमान, राजेश यादव, प्रिंस यादव, जीतेन्द्र यादव, रंजीत यादव, मनोज चौहान, साहेबलाल यादव, मनोज यादव, बिपिन यादव, एडवोकेट फैजान शेख आदि लोगों ने शाल पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएँ दिये।

डिजी यात्रा से डी-केवाईसी अभियान शुरू किया

मुंबई। डिजी यात्रा एक अत्याधुनिक सेल्फ-सॉवरिन आइडेंटिटी (एसएसआई) आधारित इकोसिस्टम है, जो फेस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी की मदद से एयरपोर्ट पर कॉन्टेक्टलेस और सीमलेस पैसेंजर प्रोसेसिंग करता है। डिजी यात्रा ने अपने डी-केवाईसी कैम्पेन की शुरूआत करने की घोषणा की है। अपने ग्राहक को न जानें' के बैनर तले यह कैम्पेन ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी को स्टोर या एक्सेस किए बिना ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की डिजी यात्रा की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। ऐसी दुनिया में जहां डेटा उल्लंघन और दुरुपयोग आम हो रहे हैं, डिजी यात्रा का दृष्टिकोण सुरक्षित और जिम्मेदार डेटा मैनेजमेंट के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करता है। डिजी यात्रा फाउंडेशन के सीईओ सुरेश खड़कभवी ने कहा, हमारा प्राथमिक लक्ष्य यात्रा को सहज और परेशानी मुक्त बनाना है। यह भी सुनिश्चित करना है कि यूजर हमारे ऐप का उपयोग करने को लेकर आश्वस्त और सुरक्षित महसूस करें। इस कैम्पेन का शुभारंभ हमारे भविष्य के विकास की तैयारी के रूप में एक बड़ा कदम है। आगे की महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं के साथ हम अपने उपयोगकर्ताओं को डिजी यात्रा के प्राइवेसी बाय डिजाइन अप्रोच के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुँचने के लिए समर्पित हैं, जो हमारी सेवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। डिजी यात्रा के संचालन के मूल में सेल्फ-सॉवरिन आइडेंटिटी के सिद्धांत और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम मानकों का पालन है। वेरिफायेबल क्रेडेंशियल्स, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों का अपने निजी डेटा पर पूरा नियंत्रण रहे। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए उच्चतम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर सभी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रूप से हटा दी जाती है। अपनी मार्केटिंग रणनीति के एक हिस्से के रूप में, कंपनी डोंटनोयुअरकस्टमर और डिजी यात्रा जैसे हैशटैग का उपयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से यूजर्स को कैम्पेन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अभियान में संतुष्ट ग्राहकों के वीडियो टेस्टिमोनियल्स और ऐप की गोपनीयता सुविधाओं और लाभों को प्रदर्शित करने वाले इन्फोग्राफिक्स भी शामिल होंगे, जो डिजी यात्रा को यात्रा का भरोसेमंद साथी बनाते हैं। 6.5 मिलियन ऐप यूजर्स और भारत भर में 24 एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस के साथ डिजी यात्रा विश्वास के महत्व पर जोर देती रही है तथा यात्रियों को एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करती है जहां सुविधा और गोपनीयता को समान रूप से प्राथमिकता दी जाती है।

गोदरेज एंटरप्राइजेस: 'कॉन्शियस कलेक्टिव 2024' के साथ जिम्मेदार और स्थायी भविष्य की ओर अग्रसर

मुंबई। दिसंबर 13-15, 2024: गोदरेज डिजाइन लैब, गोदरेज एंटरप्राइजेज का हिस्सा, इस साल कॉन्शियस कलेक्टिव का दूसरा संस्करण लेकर आ रहा है। इसका आयोजन मुंबई में 13 से 15 दिसंबर 2024 को होगा। यह खास कार्यक्रम विचारशील नेताओं, इनोवेटर्स और बदलाव लाने वालों को एक मंच पर एकत्रित करेगा, जहां वे चर्चाएं, कार्यशालाएं और रचनात्मक सत्रों के जरिए अपने विचार साझा करेंगे।

इस साल का थीम ब्रिजिंग हॉरिजन्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है, जो समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने पर जोर देगा। इसमें 20 से ज्यादा अनोखे आर्ट इंस्टॉलेशन पेश किए जाएंगे, जिन्हें आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और छात्रों ने तैयार किया है। कार्यक्रम में किताबों से जुड़े सत्र, फिल्म स्क्रीनिंग और संवादपरक कार्यशालाएं होंगी, जो दर्शकों को अपनी जीवनशैली पर नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित करेंगी। गोदरेज ने सीईईडब्ल्यू (काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर) के साथ मिलकर शहरी जीवन और स्थायित्व पर आधारित एक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है, जिसे इस इवेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। इस साल कॉन्शियस कलेक्टिव 2024 में दुनिया के जाने-माने विचारक और डिजाइन एक्सपर्ट शामिल होंगे, जैसे काइ-उवे बर्गमैन, संजय पुरी, वीरेन्द्र वाखालू, चित्रा विश्वनाथ और अयाज बसराय। ये दिग्गज असली दुनिया की चुनौतियों पर अपने अनोखे और प्रेरक समाधान साझा करेंगे। कार्यक्रम की चर्चा और बातचीत से जुड़े सत्र प्रमिती माधवजी और सोनिया बजाज ने तैयार किए हैं, जो इसे और दिलचस्प बनाएंगे कॉन्शियस कलेक्टिव का मकसद हरित और सबके अनुकूल भविष्य के लिए मिलकर काम करना है। यह इवेंट कई संगठनों के साथ साझेदारी में हो रहा है, जिनमें रॉ कोलेबोरेटिव, इंडिया क्लाइमेट कोलेबोरेटिव, चार्ल्स कोरेया फाउंडेशन जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस मंच पर क्रिएटिव कलाकारों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने मिलकर कार्यशालाएं और किताबों पर चर्चा के खास सत्र तैयार किए हैं। कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए टिकट इनसाइडर पर उपलब्ध हैं।

गोदरेज एंटरप्राइजेज का कॉन्शियस कलेक्टिव अपने पहले ही एडिशन में 4000 से ज्यादा विजिटर्स को आकर्षित कर चुका है, जहां शानदार इंस्टॉलेशन्स, इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स, और प्रमुख ब्रांड्स के साथ साझेदारी देखने को मिली। अब कॉन्शियस कलेक्टिव 2024 के साथ, गोदरेज एक ऐसा मंच तैयार कर रहा है जो नए और बेहतरीन विचारों से लोगों की जिंदगी को खुशहाल और धरती को सुरक्षित बनाए।

ढाई साल के कार्यकाल में सरकार द्वारा किये कामों का जोरदार बखान

हर कार्यकर्ता को विधायक बनने का अधिकार - जिला प्रमुख गोलाल लांडगे

डोंबिवली (उत्तरशक्ति)। अगर कोई कार्यकर्ता विधायक बनना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन महायुति में वरिष्ठों के फैसले के मुताबिक सभी घटक दल युति धर्म का पालन करेंगे ऐसा विश्वास शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख गोपाल लांडगे ने व्यक्त किया है। दरअसल कल्याण विधानसभा के भाजपा कार्यकताओं ने इस सीट पर दावा करते हुए बगावत करने की चेतावनी दी थी। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपाल लांडगे ने यह टिप्पणी की है। बतादें कि गुरुवार को डोंबिवली पूर्व के होरिजॉन हॉल में

शिवसेना (शिंदे) भाजपा और एनसीपी (अजित पवार) महायुति की संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे सेना के जिला प्रमुख गोपाल लांडगे, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र उर्फ नाना सूर्यवंशी और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शशिकांत कांबले ने पिछले पांच वर्षों में महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को मीडिया के समक्ष रखा इस दौरान उन्होंने ने लाडली बहन योजना, आरसीसी सड़क, नमो किसान महा सम्मान निधि, अटल शेतु ब्रिज, समृद्धि महामार्ग, जलापूर्ति करने वाली अमृत योजना जैसी अनेक कल्याण कारी योजनाओं का जिक्र करते हुवे सरकार की उपलब्धियां गिनाई।

इस अवसर पर शिंदे सेना के उपनेता विजया पोटे, अर्जुन पाटिल डोंबिवली शहर प्रमुख राजेश मोरे, जिला संगठक छाया वाघमारे, भाजपा के सुभाष म्हस्के, गुलाब वजे सहित शिवसेना, राकांपा और भाजपा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

वरिष्ठ पत्रकारों के साथ समाजसेवियों ने किया शिवपूजन पांडे का सम्मान

मुंबई(उत्तरशक्ति)। महानगर के वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार शिवपूजन पांडे के जन्मदिन पर आज महानगर के अनेक स्थानों पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा प्रवक्ता तथा समाजसेवी उदयप्रताप सिंह तथा युवा समाजसेवी दीपक सिंह द्वारा वाकोला, सांताक्रूज पूर्व में आयोजित कार्यक्रम में मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे, दैनिक भास्कर के संपादक विजय सिंह कौशिक, नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह, भाजपा नेता अखिलेश सिंह, साधु सिंह, पवन सिंह, जेपी सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जिला परिषद पालघर में मनाई गई महर्षि वाल्मिकी की जयंती

पालघर(उत्तरशक्ति)। जिला मुख्यालय अंतर्गत स्थित पालघर जिला परिषद कार्यालय में गुरुवार 17अक्टूबर 2024 को महर्षि वाल्मिकी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे ने उनकी प्रतिमा पर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। बतादें कि महर्षि वाल्मिकी पहली संस्कृत कविता (आदिकाव्य) के लेखक थे, जिसे दुनिया भर में महाकाव्य रामायण (भगवान राम की कहानी) के रूप में जाना जाता है, इसलिए उन्हें आदिकवि या पहला कवि कहा जाता है।

वाल्मिकी द्वारा लिखित रामायण में 24,000 श्लोक और उत्तर खंड सहित कुल 7 खंड हैं। ऐसे महान ऋषि की जयंती जिला परिषद पालघर द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी चन्द्रशेखर जगताप, जिला कृषि विकास अधिकारी सोमनाथ पिंजारी, शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) सोनाली मातेकर के अलावा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

मॉन्डेलीज इंडिया ने लाइटहाउस प्रोजेक्ट शुरू किया

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मॉन्डेलीज इंडिया ने गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की उपस्थिति में मापुसा में अपना 'लाइटहाउस प्रोजेक्ट' आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी ने पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखते हुए विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। यह पांच साल की योजना गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मापुसा नगर परिषद के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन की चुनौतियों को हल करना और सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान देना है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल किया जाएगा। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा, मुझे गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भागीदारी में मॉन्डेलीज इंडिया की सीएसआर

पहल के तहत प्लास्टिक्स सर्कुलरिटी के लिये लाइटहाउस प्रोजेक्ट लॉन्च करके बहुत खुशी हुई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मापुसा में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में बदलाव लेकर आना है और इसका फोकस मुख्य रूप से प्लास्टिक वेस्ट में चक्रीयता लाने पर होगा।

मॉन्डेलीज इंडिया के प्रेसिडेंट, समीर जैन ने कहा, पर्यावरण के अनुकूल विकास हमारी कंपनी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है, और लाइटहाउस प्रोजेक्ट प्लास्टिक को पुनः उपयोग में लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दशार्ता है, जो सरकार के कचरा प्रबंधन के दृष्टिकोण के अनुसार है। यह प्रोजेक्ट तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है झ्र व्यवहार में बदलाव, बुनियादी ढांचे का विकास, और डिजिटल नवाचार। हम कचरे के संग्रह को बढ़ाकर, स्थिरता को बढ़ावा देकर, और पूरे समुदाय को शामिल करके सर्कुलर इकोनॉमी का आधार तैयार कर रहे हैं। इस लॉन्च के दौरान, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने द फिशरमैन कास्टिंग नेट का अनावरण किया। यह कलाकृति पूरी तरह 100% रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक से बनी है और समुद्र के किनारे रहने वाले समुदायों की आजीविका को दशार्ती है। इस कार्यक्रम में गोवा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और मॉन्डेलीज के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे, जैसे कि गोवा के मंत्री एलेक्सियो सेक्वेरा, मॉन्डेलीज इंटरनेशनल इंडिया के प्रेसिडेंट समीर जैन और मॉन्डेलीज की वाइस प्रेसिडेंट ओफिरा भाटिया। यह अनूठी कलाकृति, जो गोवा के मीरामार सर्किल में स्थापित है, लोगों को पर्यावरण और धरती की रक्षा के लिए प्लास्टिक कचरे को रीसाइकिल करने और उसका दोबारा उपयोग करने का संदेश देती है।

बोईसर के प्रसिद्ध समाजसेवी विहिप पालघर जिलाध्यक्ष महावीर सोलंकी को मातृ शोक

मरणोपरांत माँ दाकुबाई ने किया नेत्रदान

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। पालघर जिला अंतर्गत स्थित बोईसर शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी,विल्डर्स एंड डेवलोपर्स रुपरजत ग्रुप और विहिप के पालघर जिलाध्यक्ष महावीर ना.सोलंकी की माताश्री दाकुबाई स्व.नानालाल सोलंकी मूल निवासी मेवाड़, रियासत कमोल, जिला उदयपुर, राजस्थान का स्वर्गवास बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को सुबह हो गया। उनकी आयु 87 वर्ष की थी। वे बहुत ही सरल,सहज और मृदुभाषी महिला थी। स्व.दाकुबाई ना.सोलंकी ने संसार से विदा होते समय 3 सुपुत्र चंदन ना. सोलंकी, गौतम ना.सोलंकी व विहिप के जिलाध्यक्ष महावीर

ना.सोलंकी समेत 2 कर्तव्यपरायण बेटियों से भरापूरा परिवार छोड़ गयी।उनके निवास 'रुप सोलंकी पैलेस' रुप रजत नगर, सिडको कालोनी के सामने तारापुर रोड, बोईसर (प.) में पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पधारे बोईसरकरों ने शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते दिंवगत आत्मा की चिरशांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बुधवार को दोपहर बाद निज निवास से मोक्षधाम बोईसर पूर्व खैरापाडा को निकली अंतिम यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में शुभचिंतक, रिस्तेदार, समाजसेवीयों द्वारा पारंपरिक रीतिरिवाजों के जरिए संपन्न हुई अंतेष्टि संस्कार के दौरान पुण्यात्मा को अंतिम भावभीनी विदाई दी गई। स्व.दाकुबाई की मरणोपरांत अंतिम ईच्छा के अनुसार जरुरतमंद अंधे व्यक्ति के आँखों की रोशनी के लिए परिजनों ने उनकी आँखें रोटरी बोरीवली आई बैंक को दान किया।

नागरी संरक्षण दल द्वारा आयोजित नागरी संरक्षण स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण शिविर का समापन आज

पालघर(उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र सरकार गृह विभाग (विशेष) के पालघर जिला के नागरी संरक्षण दल की ओर से नागरिकों को नागरी संरक्षण स्वयंसेवक के तौर पर तैयार करने हेतु पांच दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ सोमवार 14 अक्टूबर 2024 को पालघर जिले के बोईसर शहर के पास स्थित सरावली ग्राम पंचायत भवन के सभागृह में किया गया था। यह प्रशिक्षण शिविर 14 अक्टूबर से नित्य आयोजित किया जा रहा है। जिसका समापन शुक्रवार 18अक्टूबर 2024 को किया जायेगा। प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता सहायक उप नियंत्रक के.आर. कुरकुटे, विभागीय क्षेत्ररक्षक पालघर(वाडा) नीलेश वझे,

विभागीय क्षेत्ररक्षक नरेश म्हस्के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार के सुवर्ण नियम, प्रथम उपचार के तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं इमरजेंसी के दौरान घायल अथवा बीमार व्यक्तियों का विभिन्न तरीकों से उपचार करने के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान विभागीय क्षेत्ररक्षक नरेश म्हस्के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण शिविर की मुख्य आयोजिका सुवर्णा महामुनि, वित्तीय सलाहकार उज्वला कोकणे, समाजसेवी पद्माकर महामुनि, स्वयंसेवक शैलेंद्र मिश्रा, पत्रकार अजीत सिंह के अलावा बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे।

बविआ कार्यकताओं ने मनाया पालघर जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ घरत का जन्मदिन

पालघर(उत्तरशक्ति)। बहुजन विकास आघाड़ी के जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ घरत का 50वां जन्मदिन मंगलवार 15 अक्टूबर 2024 को बविआ कार्यकताओं को ओर से बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी बोईसर के कार्यकर्ता वीरेंद्र और चर्च के सदस्यों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने बोईसर मधुर होटल के पास स्थित उनके जनसम्पर्क कार्यलय पहुंचे। विरेंद्र ने विश्वनाथ घरत को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके साथ आगे भी सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु चर्चा की। इस दौरान विरेंद्र ने बविआ जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ घरत को चर्च का परिचय देते हुए कहा कि चर्च ऑफ गॉड की शुरूआत 1964 में कोरिया में हुई और इस वर्ष वह अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत सहित 175 देशों के 7800 क्षेत्रों में 37 लाख विश्वासी हैं। जो बाइबल के अनुसार पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वे प्रथम चर्च ऑफ गॉड की तरह,

जिसमें 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह, पतरस, यूहन्ना और पौलुस जैसे प्रेरित भाग लेते थे। नई वाचा के फसह सहित तीन बार में सात पर्व के साथ सब्त मनाते हैं। परमेश्वर की शिक्षा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, के अनुसार सदस्यों ने 29000 बार सामाजिक योगदान गतिविधियों को अंजाम दिया है। बविआ जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ घरत के जन्मदिन के मौके पर बविआ पदाधिकारी एवं कार्यकताओं समेत अनेक शुभचिंतक कार्यालय पहुंचकर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट देते हुए जन्मदिन की बधाई दी।

3 महीने के शिशु में सफल 'एंडोस्कोपिक क्रेनियोसायनोस्टोसिस' सर्जरी की

नवी मुंबई। अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई में क्रेनियोसायनोस्टोसिस के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह एक दुर्लभ स्थिति होती है, जिसमें शिशु की सिर की हड्डियां समय से पहले जुड़ जाती हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी डॉ. सुमीत पवार ने 3 महीने के शिशु पर यह प्रक्रिया की। 2000 जन्मों में से 1 में यह दुर्लभ स्थिति होती है, मस्तिष्क के विकास को रोकती है। इसका समय पर पता लगाना जरूरी होता है, क्योंकि समय पर इलाज से बड़ी सर्जरी की आवश्यकता को रोका जा सकता है।अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई में एक शिशु को लाया गया क्योंकि माता-पिता ने देखा कि शिशु का चेहरा, विशेष रूप से भौहें सममित नहीं थीं। जांच के बाद पता चला कि, शिशु को क्रेनियोसायनोस्टोसिस यह दुर्लभ जन्मजात बीमारी थी, जिसमें शिशु की सिर की हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है, जिससे सिर की सामान्य रूप से बढ़ने की क्षमता सीमित हो जाती है, और सिर का आकार असामान्य हो जाता है। इसे अगर ठीक नहीं किया जाता है, तो विकासशील मस्तिष्क पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे दिमाग के विकास में देरी हो सकती हैं। समय पर सर्जरी करने से, सिर के आकार को ठीक कर सकता है, मस्तिष्क पर दबाव

को कम कर सकता है और सामान्य वृद्धि और विकास हो सकता है।

डॉ. सुमीत पवार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी, अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ने कहा,₹जल्द से जल्द, खासकर जन्म के बाद पहले तीन महीनों में, निदान जरूरी है, क्योंकि इससे हम 3-6 महीने की उम्र के बीच सिर्फ.2.5 सेमी चीरा लगाकर एंडोस्कोपिक तरीके से प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर निदान में देरी होती है और शिशु 6-9 महीने का है, खोपड़ी खोलके सर्जरी की आवश्यकता होगी, जिसमें 20 सेमी का बहुत बड़ा चीरा लगाना होगा। इतनी कम उम्र में, यह गंभीर जोखिम वाली एक बड़ी सर्जरी बन जाती है। हमारा लक्ष्य ओपन स्कल सर्जरी की आवश्यकता से बचने के लिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना और शिशु में अधिक सुरक्षित और कम इन्वेसिव सुधार सुनिश्चित करना है। हम इस सर्जरी के सफल परिणाम से बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सफलता इस क्षेत्र में इस स्थिति वाले शिशुओं पर इस तरह के और अधिक इलाजों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रक्रिया में खून कम से कम बहा और शिशु को आईसीयू में सिर्फ.एक रात रखना पड़ा।₹

सर्जरी के बाद, शिशु को एक कस्टम 3डी-प्रिंटेड हेलमेट पहनाया गया । इस हेलमेट को अगले दो वर्षों में सिर के विकास को निर्देशित करने और उसके आकार को सही करने के लिए डिजाइन किया गया है। नियमित फॉलो-अप विजिट से यह सुनिश्चित होगा कि हेलमेट को लगभग सामान्य सिर के विकास के लिए उचित रूप से एडजस्ट किया गया है।श्री मृगेंद्र प्रताप, भोपाल से आए हुए इस शिशु के पिता ने बताया, ₹हमने हमारे शिशु में चेहरे पर असामान्यताओं को देखा और तुरंत सही विशेषज्ञ की तलाश शुरू कर दी। डॉ. सुमित के साथ हमारी चर्चा के दौरान ही हमें क्रेनियोसायनोस्टोसिस के बारे में पता चला। हम उपचार में देरी का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि इससे हमारे शिशु का बढ़ना और विकास प्रभावित हो सकता था।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* संरक्षकः सुरेश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
* प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालयः
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक) नियर जॉनसन हाऊस, शाप नंबर - 21, उन्नति सी.एच.एस. सेनापति बापट मार्ग, माहिम (वेस्ट) मुंबई-400016
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37

स्वामी- शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविन्द्रनाथ प्रजापति द्वारा एस.आर. पब्लिकेशन मोहन अर्जुन कम्पाउंड गोडाउन नं.-08,09,10 नियर घर्टनपाड़ा वैशाली नगर लास्ट बस स्टाफ दहिसर (ई.) मुंबई 400068 से मुद्रित एवं 103, प्रथम फ्लोर बी विंग एयरपोर्ट ब्यू सी.एच.एस. लि. वीर मकरन्द घानेकर मार्ग आजाद रोड फायर विग्रेड विले पारले (ई.) जिला मुंबई (महाराष्ट्र) से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 *संपादक- ओमप्रकाश रविन्द्रनाथ प्रजापति, इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदायी तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः नियर जॉनसन हाऊस, शाप नंबर - 21, उन्नति सी.एच.एस. सेनापति बापट मार्ग, माहिम (वेस्ट) मुंबई-400016 * मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com,

अभियान चलाकर दोहरा के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की किया समीक्षा बैठक

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक बुधवार देर सायं संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उप जिलाधिकारी और बाट माप विभाग की उपस्थिति में सैंपल की जांच करने जाएंगे।

जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से जानकारी ली कि एक अप्रैल से अब तक कितने सैंपल लिए गए हैं और उसमें कितने सैंपल पास और कितने फेल हुए है। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर दोहरा के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करें और दोहरा खाने से होने वाले नुकसान के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों को जागरूक करने हेतु कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने व्यापारियों की भी कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने खाद्य एवं विपणन अधिकारी को निर्देशित किया कि धान खरीद की तैयारी कर लें।

इसके पश्चात जिलाधिकारी ने डीजी शक्ति, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निर्गत, निर्विवाद उत्तराधिकार की माह अगस्त 2024 की रैंकिंग की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी उपजिलाधिकारी अभियान चलाकर पुराने मुकदमों का निस्तारण कराएं और अच्छा कार्य करने वाले लेखपालों को बुलाकर उनको सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन करें। सबसे अधिक विवाद वाले गांवों में जाकर मामले का निस्तारण कराएं। निवास और आय, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अच्छा कार्य किए जाने पर सभी उप जिलाधिकारियों और सम्बन्धित कर्मचारियों की प्रशंसा किया। उन्होंने निर्देश दिया कृषक दुर्घटना सहायता योजना में प्रगति लाई जाए। आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का ससमय गुणवत्तापुर्ण निस्तारित करें।

इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान, नगर मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिला अस्पताल में समय से नहीं बैठते डॉक्टर

रियाजुल हक संवाददाता नगर

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। ज़िला अस्पताल का यह हाल है कि जहां डाक्टर प्रभात सिंह अपने चेंबर में 10:30 पर सुबह आते हैं और 11:30

दूर दराज से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को करना पड़ता है दिनभर इंतजार

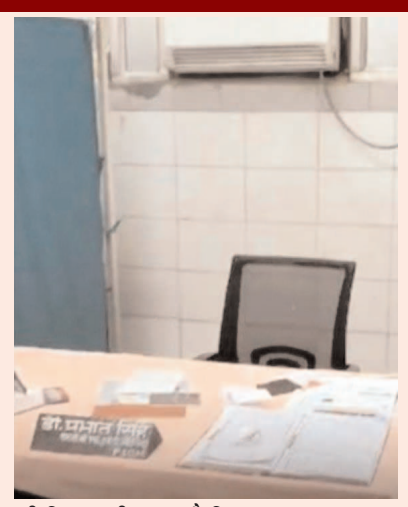

अपने चेंबर से चले जाते हैं जबकि दूर दराज से आए मरीजों को घण्टों सिक्योरिटी वालो द्वारा कतार में खड़ा कराया जाता है। यह कहकर कि डाक्टर साहब राउंड पर गये है।और मरीज इस उम्मीद में दोपहर दो बजे तक रहते है कि डाक्टर साहब अब आएंगे, अब आएंगे और वो वही भूखे प्यासे बैठे रहते है। लेकिन होता वही है कि दूर दराज से आए विभिन्न बीमारियों के रोगी और उनके तिमारदार थके-हारे निराश होकर लौटा दिए जाते हैं। यदि कोई यह पूछने की हिम्मत भी करता है कि डाक्टर साहब कब आएंगे तो सिक्योरिटी और वहा मौजूद स्टाफ द्वारा मरीजों से बद्तमीजी किया जाता है। जबकि डाक्टर साहब ना किसी मिटींग में होते हैं ना ही राउंड पर अपितु डाक्टर साहब अपने निजी कार में बैठ कर 12:30 पर ही निकल जाते हैं। सीसी टीवी कैमरा

डॉक्टर के खाली पड़े चेंबर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

भी परिसर में है निगरानी हेतु फुटेज भी मिल जाय किन्तु कोई फायदा नहीं है क्योंकि कहीं कोई सुनवाई नहीं है।

इस बाबत जब जिला अस्पताल के मुख्य चिकत्सा अधीक्षक से फोन द्वारा संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका नंबर पहुंच से बाहर बता रहा था। वायरल वीडियो जिला अस्पताल का तो है लेकिन किस समय और किस दिनांक का है, इसकी पुष्टि आपका अपना अखबार उत्तरशक्ति नहीं करता।

सर सैय्यद डे पर मरीजों को बांटे गये फल

डॉ.इम्तियाज अहमद ज़िला संवाददाता

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। सर सैय्यद डे पर मरीजों को बांटे गये फल रक्तदान करके पेश किया स सैय्यद अहमद खान को खिराज ए अकीदत सर सैय्यद डे पर ए.एम.यू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जौनपुर ने जिला चिकित्सालय में मरीजों और उनके तीमारदारों को फल वितरित किये। और साथ ही डॉ. सैफ हुसैन खान एवं डॉ. फैज खान, डॉ. नदीम खान ने रक्तदान करके सर सैय्यद अहमद खान को उनकी 207वें जन्मदिन पर खिराज ए अकीदत पेश किया। ए.एम.यू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जौनपुर के अध्यक्ष डॉ. सैफ हुसैन खान ने कहा कि जिला अस्पताल में जो गरीब मरीज आते हैं उनके लिये फल वितरण का कार्यक्रम किया गया और साथ ही सदस्सयों ने रक्तदान किया क्योंकि इस समय डेंगू की बीमारी चल रही है जिसके लिये प्लाज्मा, प्लेट लेट, रक्त की आवश्यकता होती है इसके लिये हमारी एसोसिएशन काफी सक्रिय

है। महासचिव शभासद शाहनवाज मंजूर ने कहा कि स सैय्यद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को हुआ उनका मिशन था कि कौम के बच्चों के एक हाथ में कुरआन और दूसरे हाथ में साइंस हो इसके लिये पूरे जीवन वोह प्रयासरत रहे आज हम लोगों को भी उनके मिशन को अपना मिशन समझकर लोगों को एक बार पुनः शिक्षा के बंधन में बांधने की आवश्यकता है तभी उनको सच्ची श्रद्धाजली होगी। इस अवसर पर डॉ. फहीम खान, डॉ. मोहम्मद फैज, इंजी. काजी फैज अहमद, दानिश अब्बास, मोहम्मद आरिफ खान, आरिफ अब्बास, गजनफर अली, जफर अब्बास बॉबी, एजाज मेहंदी, आरिफ कुरैशी, मोहम्मद आबिद, साकिब सिद्दीकी उपस्थित रहे।

महर्षि बाल्मीकि का जीवन तपस्या और ज्ञान का प्रतीक: राकेश मौर्य

जौनपुर,(उत्तरशक्ति)।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी जौनपुर के जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य की अध्यक्षता में नगर के मंगलम लॉन मियांपुर में दिन में 11 बजे संस्कृत रामायण के रचयिता, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। सर्वप्रथम उपस्थित पार्टी जनों ने महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तत्पश्चात गोष्ठी आयोजित कर उनके विषय में विचार व्यक्त किया। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की जिसे उनके नाम पर वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है जिन्होंने कठिन साधना के बाद महर्षि का पद प्राप्त किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दीपचंद सोनकर पूर्व मंत्री श्री राम यादव पूर्व एमएलसी ललन प्रसाद यादव पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव ने कहा कि जब रत्नाकर ने नारद मुनि से अपने पाप कर्मों के परिणाम के बारे में जाना। तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान श्रीराम के नाम का जाप करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे ज्ञानी और महापुरुषों को याद करके उनके सिद्धांतों और आदर्शों को ग्रहण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गोष्ठी को प्रदेश सचिव क्रमशः हिसामुद्दीन शाह, सुशील दुबे वरिष्ठ नेता रुखसार अहमद, ज़िला उपाध्यक्ष गण क्रमशः महेंद्र यादव, हीरालाल विश्वकर्मा, केशजीत यादव, राजेंद्र यादव टाइगर, इरशाद मंसूरी, आलोक त्रिपाठी लकी, राहुल त्रिपाठी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम नारायण बिंद, विधानसभा अध्यक्ष गण क्रमशः वीरेंद्र यादव सदर, नंदलाल यादव जफराबाद, रामू मौर्य एडवोकेट मडियाहू, अशोक निषाद महासचिव बदलापुर, डा. जंगबहादुर यादव, हरिश्चंद्र प्रभाकर, नीतू शर्मा, श्याम यादव तपस्वी, धर्मराज यादव आदि ने संबोधित किया। गोष्ठी का संचालन ज़िला महासचिव आरिफ हबीब ने किया। जयंती समारोह में मुख्य रूप से ज़िला सचिव गुलाब यादव रीठी, अल्पसंख्यक सभा की प्रदेश सचिव डॉ शबनम नाज, जयप्रकाश यादव प्रिंसु, डॉ शिवजीत यादव, अजय मौर्य, अशोक यादव नायक, गुड्डू सोनकर, आनंद गुप्ता, पंडित जितेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र सोनकर, सुनील बासुदेव यादव, अरविंद सोनकर, अभय दुबे, अमजद अली, दीना यादव, रविशंकर यादव सहित अन्य सपाजन उपस्थित रहे।

सल्तनत बहादुर डिग्री कालेज में बालिकाओं को किया जागरूक

मिशन शक्ति के अंतर्गत 90 दिवसीय अभियान

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। शासन के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक डा० अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में मिशन शक्ति के अंतर्गत 90 दिवसीय अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शैलेन्द्र कुमार सिंह

के दिशा निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी बदलापुर आयुष श्रीवास्तव व प्रभारी निरीक्षक बदलापुर विनोद कुमार मिश्र की उपस्थिति में थाना बदलापुर व पेशी बदलापुर पर नियुक्त महिला आरक्षियों द्वारा लगभग 1200 महिलाओं को सल्तनत बहादुर डिग्री कालेज में सभा/गोष्ठी करके महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया व समस्त हेल्पलाइन नं0 1090, 112, 1930, 108, 102, 181, 1076 से अवगत कराया गया एवं साईबर क्राईम से बचने के उपाय बताते हुए मिशन शक्ति के पम्पलेट प्रदान किया गया ।

मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने मनाया सर सैयद डे

जौनपुर,(उत्तरशक्ति)। मियांपुर की मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित मदरसे में सर सैयद अहमद की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिसमें सर सैयद अहमद खान के जीवन परिचय को बताया गया उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा के प्रति किए गए योगदान को बच्चों को बताया गया। मौलाना अलकमा शाहिद अख्तर एवं बख्तियार आलम ने अपने वक्तव्य दिए कार्यक्रम में मदरसे के बच्चे एवं मोहल्ले वासियों ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया बख्तियार आलम ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

अशोक कुमार बने प्रधान संघ के नये अध्यक्ष

खेतासराय,जौनपुर(उत्तरशक्ति)। शाहगंज ब्लाक के ग्राम प्रधानों ने गुरुवार को सोंधी कार्यालय के सभागार में प्रधान संघ कमेटी भंग कर नई कमेटी का गठन कर लिया। नई कमेटी में प्रधानों ने ग्राम पंचायत सैफपुर के प्रधान अशोक कुमार यादव को सर्वसम्मति से अपना नया संघ का अध्यक्ष चुन लिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद यादव से अधिकतर प्रधान नाराज चल रहे थे। प्रधानों ने एक जुट होकर नया अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए ब्लाक सभागार में प्रधान मो.इसराइल की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। बैठक में कोरम पूरा होने पर प्रधानों एक स्वर में अशोक कुमार यादव को प्रधान संघ का अध्यक्ष घोषित किया। वहीं उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी परमानंद यादव और संगीता देवी के प्रतिनिधि राजकुमार को दिया गया। जबकि संतोष सोनकर को महामंत्री बनाया गया है। सचिव की जिम्मेदारी चंद्रशेखर राजभर तथा कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रधान प्रतिनिधि भीमचंद राजभर और सेराज अहमद को दी गई। प्रधान संघ की नई कार्यकारिणी गठन होने के बाद ग्राम प्रधानों ने नव नियुक्त प्रधान संघ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान कृपाशंकर राजभर, मोओ साजिद, गुलाब चंद्र, मोओ अयाज, रेखा देवी, रीना, बाबर सिद्दीकी, चंद्र शेखर थानेदार यादव, आदि लोग उपस्थित रहे।

ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक संपन्न

खेतासराय,जौनपुर(उत्तरशक्ति)। विकास खण्ड शाहगंज के सभागार में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ जितेंद्र प्रताप सिंह ने की।

अग्रणी जिला प्रबंधक शंकर चंद्र सामंत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में क्षेत्र की सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधक और बैंक सखियों ने भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल), बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अटल पेंशन योजना पर चर्चा हुई। एडीओ आईएसबी संजय श्रीवास्तव ने स्वयं सहायता समूहों के लिए सीसीएल का लाभ समझाते हुए कहा कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन में सहायक साबित हो रही है।

अग्रणी जिला प्रबंधक शंकर चंद्र सामंत ने सभी बैंक शाखाओं से इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन एडीओ आईएसबी संजय श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर एफ एल सी इंचार्ज कमलेश यादव,ब्लॉक मिशन प्रबंधक संदीप दिवेदी, प्रियंकेश प्रजापति, शाहगंज क्षेत्र के सभी बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधक और बैंक सखियां उपस्थित रहीं।

स्वर्ण व्यवसायी विक्रांत सेठ को व्यापारियों ने दी श्रद्धांजलि

चन्दवक,जौनपुर(उत्तरशक्ति)। स्वर्ण व्यवसायी विक्रांत सेठ की हत्या मामले को लेकर बजरंग नगर बाजार में शोक सभा का आयोजन किया गया। बजरंगबली मंदिर परिसर में आयोजित सभा स्थानीय

व्यापारियों ने कैंडिल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा का नेतृत्व व्यापार मंडल के बजरंग नगर अध्यक्ष डॉ नरसिंह बहादुर सिंह ने किया। सभा में कृष्ण मोहन चौरसिया, रामसम्हार सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, विकास सिंह आशु, विनोद सेठ, मनीष सेठ, अजय सिंह, शीतलदान सिंह, डॉ धर्मराज, नीलेश कुमार सिंह,रामचंद्र सिंह सारनाथ,अनुपम सिंह, शिवशंकर सिंह मंदिर के पुजारी संजय दुबे आदि रहे। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह चन्दवक थाना क्षेत्र के कोइलारी बाजार से लौटते समय एक बदमाश ने गोली मार दिया था। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। व्यापारी की मौत से साथी व्यापारियों में आक्रोश है।

पागल कुत्ते ने रात में सो रहे लगभग एक दर्जन लोगों को काटा

डॉ.एस.के.मिश्र

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। आराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के पनियरा गांव में बृहस्पतिवार की बीती रात में एक पागल कुत्ते ने गांव में रात में सो रहे लगभग एक दर्जन लोगों सहित पशुओ को भी बेरहमी से काट लिया। गांव में उक्त पागल कुत्ते के आतंक से भयभीत ग्रामीणों ने उक्त पागल कुत्ते को घेराबंदी कर मार गिराया गया उसके बाद राहत की सांस ली। सुबह होते ही पागल कुत्ते से शिकार हुए सभी घायल लोग जख्मी स्थित में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। जहां पर डॉक्टरों द्वारा सभी घायलों को एंटी रैबीज का टीका लगाया गया। लेकिन कुछ व्यक्तियों को कमर से ऊपर कुत्ते ने काटा था जिसके लिए इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन की जरूरत महसूस हुआ तो उनको डॉक्टरो ने बीएचयू रेफर किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ नवीन सिंह ने बताया कि हमारे सीएचसी पर एंटी रैबीज टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन की यहां पर राजकीय सप्लाई नहीं है इसलिए बीएचयू के लिए रेफर किया गया।

परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराए सर्टिफिकेट चयनित हज यात्री

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अनीता ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ के द्वारा हज-2025 की हज यात्रा हेतु उत्तर प्रदेश से जाने वाले समस्त हज आवेदकों का चयन हो गया है। चयनित होने की सूचना हज यात्रियों को भेज दी गयी है। चयनित हज यात्रियों को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस सर्टिफिकेट 23 अक्टूबर 2024 तक सरकारी एलोपैथिक पद्यति के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कराकर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना है। हज कमेटी आफ इण्डिया का सकुर्लर-9, 08 अक्टूबर 2024 सुलभ संदर्भ हेतु निर्धारित प्रारूप के साथ संलग्न करते हुए जनपद जौनपुर में चयनित-62 हज यात्रियों मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस सर्टिफिकेट 23 अक्टूबर 2024 तक सरकारी एलोपैथिक पद्यति के चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर चिकित्सीय प्रमाण पत्र हज यात्रियों को जारी करायें।

इनोवेटिव आईडिया के लिए दस हजार का पुरस्कार

जौनपुर,(उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन एवं विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इंडस्ट्री- एकेडेमिया इंटरफेस के तहत एक व्याख्यान का आयोजन इन्क्यूबेशन एवं इनोवेशन केंद्र पर किया गया।। अतिथि शेखर आनंद ने थिंक लाइक एंटरप्रेन्योरशिप विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि एक प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, फीडबैक और उसके बाद उस आइडिया को प्रोडक्ट में परिवर्तित करके आप एंटरप्रेन्योर की दिशा में बढ़ सकते हैं लेकिन यदि आपके प्रोडक्ट के लिए बिजनेस मॉडल नहीं है तो आपका आईडिया से प्रोडक्ट किसी काम का नही होगा। बिजनेस मॉडल के लिए अनुदान की आवश्यकता होती जिसके लिए सरकार के विभिन्न फंडिंग एजेंसी जैसे बायरैक , बिग ग्रांट, स्टार्टअप, एमएसएमई इत्यादि से इनोवेटिव आईडिया के लिए अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर शेखर आनंद ने इनोवेटिव आईडिया के लिए किसी एक विद्यार्थी को दस हजार रुपए पुरस्कार स्वरुप देने की घोषणा भी की । धन्यवाद ज्ञापन डॉ मनीष कुमार गुप्ता ने किया ।

प्रधानमंत्री वाराणसी में करेंगे आधुनिक आर झुनझुनवाला शंकरा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का उद्घाटन

डॉ.एस.के.मिश्र

वाराणसी,(उत्तरशक्ति) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी में आधुनिक आर झुनझुनवाला शंकरा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। जिसकी स्थापना भारत के अग्रणी आई केयर सर्विस प्रदाताओं में से एक शंकरा आई हॉस्पिटल द्वारा, प्रमुख निवेशक राकेश झुनझुनवाला परिवार और शंकरा आई फाउंडेशन, यूएसए के सहयोग से की गई है। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों को विश्वस्तरीय आई केयर उपचार उपलब्ध कराएगा। अस्पताल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल, जगदगुरू शंकरा विजयेन्द्र सरस्वती स्वामीगल, 70वें जगदगुरू पीठाधिपति- कांची कामकोटि पीठम, कांचीपुरम, तमिलनाडु की मौजूदगी में होगा। एस वी बालासुब्रमण्यम, चेयरमैन, एसईएफआई, पद्मश्री डा.आर.वी. रमणी, संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी, शंकरा आई फाउन्डेशन इंडिया, मुरली कृष्णामूर्ति, एक्जक्टिव चेयरमैन शंकरा आई फाउन्डेशन, यूएसए और रेखा झुनझुनवाला,सदस्य- बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी का यह अस्पताल देश में शंकरा का 14वां अस्पताल है।जो हर साल सबसे गरीब मरीजों की 30,000 निःशुल्क आई सर्जरियां करेगा। अस्पताल की स्थापना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दक्षिण भारत (तमिलनाडु) का कांची कामकोटि मेडिकल ट्रस्ट, जो शंकरा आई हास्पिटल को सहयोग प्रदान करता है ने ऐतिहासिक-सांस्कृतिक महत्व के शहर वाराणसी में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस विश्वस्तरीय आई केयर सुविधा की स्थापना रु 110 करोड़ के निवेश से की गई है। इसमें 30 हजार सर्जरियां करने की क्षमता है।अस्पताल में 9 आपरेशन थिएटर्स के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी। अपने सुगम संचालन को सुनिश्चित करने तथा सबसे गरीब मरीजों को आई केयर एवं उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल क्रास-सब्सिडाइजेशन माडल (75:25) पर काम करेगा, जिसमें भुगतान करने वाले मरीजों से आई धनराशि का उपयोग जरूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए किया जाएगा। (हमारे 25 फीसदी लाभार्थी 75 फीसदी लाभार्थियों की निःशुल्क सर्जरियों की लागत का वहन करेंगे)। डा.आर.वी. रमणी, संस्थापक एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, शंकरा आई फाउंडेशन ने कहा, ह्यह्यभारत में नेत्रहीनों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। इनमें से 80 फीसदी मामलों में अंधेपन को रोका जा सकता है। शंकरा आई हॉस्पिटल में हम सभी को गुणवत्तापूर्ण आई केयर उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हमने 2030 तक देश भर में 5 लाख फ्री सर्जरियां करने का लक्ष्य रखा है। अस्पताल अनूठे हाइब्रिड माडल पर काम करेगा। जिसके तहत न सिर्फ वाराणसी बल्कि उत्तर प्रदेश के आस-पास के गांवों एवं जिलों से आए मरीजों को भी सब्सिडी के साथ सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए संसाधन उन मरीजों से जुटाए जाएंगे जो इलाज का खर्च उठा सकते हैं। शंकरा आई फाउन्डेशन खासतौर पर उत्तर भारत में वंचित क्षेत्रों में अपने विस्तार के लिए प्रयासरत है और सुनिश्चित करता है कि अस्पताल की आधुनिक आईकेयर सेवाएं देश के सबसे जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचें।

साड़ी कारोबारी से ठगी मामले में लॉरेंस गैंग के हैकर आशीष बिश्नोई को मिली जमानत

वाराणसी,(उत्तरशक्ति)। वाराणसी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी और अंतरराष्ट्रीय हैकर आशीष बिश्नोई को जिला और सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। आशीष पर एक साड़ी कारोबारी से निवेश के नाम पर 27.50 लाख रुपए की साइबर ठगी का आरोप है। यह जमानत बुधवार रात को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विनोद कुमार की अदालत द्वारा दी गई। अदालत ने आशीष की जमानत को मंजूर करते हुए उसे दो जमानतदारों और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष ने दलीलें पेश कीं, लेकिन सबूतों के अभाव में जमानत स्वीकृत कर दी गई। आशीष बिश्नोई राजस्थान के अनूपगढ़ का निवासी है और यह अंतरराष्ट्रीय हैकर गिरोह का सदस्य है। उसके गिरोह का उपयोग लॉरेंस बिश्नोई और दुल्लू गैंग जैसे कई अन्य गिरोह करते थे। साइबर ठगी के इस मामले की जानकारी तब मिली जब वाराणसी की साइबर टीम ने पिछले दिनों आशीष को उसके तीन अन्य साथियों के साथ राजस्थान के श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया। आशीष ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का रिश्तेदार बताया था। इसके खिलाफ महमूरगंज सिगरा निवासी वादी अजय कुमार श्रीवास्तव ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 10 सितंबर को डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में साइबर थाने की टीम ने राजस्थान के सूरतगढ़ से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें आशीष के अलावा हनुमानगढ़ जिले के प्रिंस खोड, बिकानेर के हरीश बिश्नोई और मनदीप सिंह शामिल थे। डीसीपी के अनुसार, आशीष बिश्नोई गैंग का लीडर है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैकिंग में माहिर है। वह लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गिरोहों की मदद करता था। जिससे बड़े वेबसाइटों को हैक करने और पैसे की निकासी में सहायता मिलती थी। आरोप है कि दुल्लू गैंग के सदस्य उसे जबरन हैकिंग कराते थे। आशीष ने पाकिस्तान सीमा के निकट एक ठिकाना बनाया था, जहां से वह साइबर ठगी के नेटवर्क को संचालित करता था। उसके गिरोह ने अब तक 10 हजार करोड़ रुपए की ठगी की है। आरोपियों के पास से डेबिट कार्ड, चेकबुक और क्यूआर कोड बरामद हुए थे ।